

इंडियन एल्युमीनियम केबल्स लिमिटेड

बनाम

हरियाणा राज्य

2 अप्रैल, 1976

[ए.एन. राय, (सीजे) एम. हमीदुल्लाह बेग, जसवंत सिंह, जे.जे.]

कर दायित्व से छूट- सामान्य कर छूट- केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम (74/1956)- धारा 8(2 ए) और तत्संबंधी स्पष्टीकरण- "आम तौर पर कर से छूट" का अर्थ। पंजाब बिक्री कर अधिनियम- धारा 5(2)(ए)(iv)- धारा के तहत दी गई छूट की प्रकृति- चाहे निर्दिष्ट परिस्थितियों में या निर्दिष्ट शर्तों के तहत।

पंजाब बिक्री कर अधिनियम की धारा 5(2)(ए)(iv) के तहत "कर योग्य टर्नओवर" का मतलब किसी भी अवधि के दौरान डीलर के सकल टर्नओवर का वह हिस्सा है जो उसमें से कटौती के बाद बचता है, उस अवधि के दौरान उसका कारोबार और भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910 के तहत दिए गए लाइसेंस या मंजूरी के तहत जनता को विद्युत ऊर्जा की आपूर्ति करने वाले किसी भी उपक्रम को ऐसी ऊर्जा के उत्पादन या वितरण में उपयोग के लिए वस्तुओं की बिक्री।"

केंद्रीय बिक्री कर की धारा 8 के तहत, प्रत्येक डीलर जो अंतरराज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान सरकार को कोई सामान बेचता है; या उपधारा (3) में निर्दिष्ट विवरण के सरकारी सामान के अलावा किसी पंजीकृत डीलर को बेचता है, तो अधिनियम के तहत कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा, जो उसके कारोबार का तीन प्रतिशत होगा। धारा 8(2 ए) इस प्रकार है:-

"धारा 6 की उपधारा (1 ए) या इस धारा की उपधारा (1) या उपधारा (2) में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के तहत एक डीलर द्वारा अपने टर्नओवर पर देय कर, जहां तक टर्नओवर या उसका कोई हिस्सा किसी सामान की बिक्री, बिक्री या, जैसा भी मामला हो, की खरीद से संबंधित है, जो उपयुक्त राज्य के बिक्री कर कानून के तहत, आम तौर पर कर से छूट, या आम तौर पर तीन प्रतिशत से कम दर पर कर के अधीन, (चाहे कर या शुल्क या किसी अन्य नाम से कहा जाए), शून्य होगा या जैसा भी मामला हो, कम दर पर गणना की जाएगी।

स्पष्टीकरण: इस उपधारा के प्रयोजन के लिए किसी भी सामान की बिक्री या खरीद को आम तौर पर उपयुक्त राज्य के बिक्री कर कानून के तहत कर से छूट नहीं माना जाएगा,

यदि कानून के तहत ऐसे सामान की बिक्री या खरीद को छूट दी गई है केवल निर्दिष्ट परिस्थितियों में या निर्दिष्ट शर्तों के तहत या ऐसे सामानों की बिक्री या खरीद पर लगाए गए कर से छूट केवल निर्दिष्ट परिस्थितियों में या निर्दिष्ट शर्तों के तहत दी जाती है या ऐसे सामानों की बिक्री या खरीद पर निर्दिष्ट चरणों में माल के कारोबार के संदर्भ में या अन्यथा कर लगाया जाता है।"

अपीलकर्ता दिल्ली इलेक्ट्रिक सप्लाइ अंडरटेकिंग खंभों और केबलों के आपूर्तिकर्ता थे और बिक्री अंतरराज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान की गई थी और माना जाता है कि धारा 5(2)(ए)(iv)' के तहत राज्य बिक्री कर के तहत छूट दी गई थी। राज्य ने केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की धारा 8 के तहत कर का आकलन इस आधार पर किया कि राज्य अधिनियम की धारा 5(2)(ए)(iv) के तहत दी गई छूट केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम धारा 8(2 ए) के स्पष्टीकरण के अंतर्गत आती है। उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि विद्युत ऊर्जा की आपूर्ति करने वाले उपक्रम की बिक्री आम तौर पर राज्य अधिनियम की धारा 5(2)(ए)(iv) के साथ पढ़े गए केंद्रीय अधिनियम की धारा 8 (1 ए) के अर्थ में कर से मुक्त नहीं थी।

न्यायालय ने विशेष अनुमति द्वारा अपील खारिज करते हुए अभिनिर्धारित किया कि: (1) सामान्य छूट का मतलब है कि केंद्रीय बिक्री कर लगाने से समान छूट उपलब्ध होने से पहले वस्तुओं को कर से पूरी तरह मुक्त किया जाना चाहिए। जहां कराधान से छूट शर्तों द्वारा या कुछ परिस्थितियों में प्रदान की जाती है, वहां आम तौर पर कर से कोई छूट नहीं होती है। राज्य अधिनियम की धारा 6 छूट की बात नहीं करती बल्कि कर मुक्त वस्तुओं से संबंधित है। धारा 6 उन निर्दिष्ट वस्तुओं से संबंधित है जिन पर कोई कर देय नहीं है। राज्य अधिनियम की धारा 5 इस बात से संबंधित है कि डीलर के कर योग्य टर्नओवर में किसे शामिल नहीं रखा जाना चाहिए। दोनों धाराएँ उन वस्तुओं से संबंधित हैं जिन पर बिक्री कर नहीं लगता है। केंद्रीय अधिनियम की धारा 8(2 ए) वस्तुओं को अंतरराज्यीय बिक्री कर से छूट देती है, जहां राज्य के कर कानून ने उन्हें बिक्री कर से छूट दी है। केंद्रीय अधिनियम की धारा 8(2 ए) की व्याख्या उस छूट को हटा देती है जहां यह सामान्य नहीं है और निर्दिष्ट परिस्थितियों में या निर्दिष्ट शर्तों के तहत दी गई है। राज्य अधिनियम की धारा 5(2)(ए)(iv) में निहित प्रावधान उन बिक्री को बाहर करते हैं जो निर्दिष्ट परिस्थितियों या निर्दिष्ट शर्तों के तहत की जाती हैं। निर्दिष्ट परिस्थितियाँ यह हैं कि बिक्री भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910 के तहत दिए गए लाइसेंस या मंजूरी के तहत जनता को विद्युत ऊर्जा की आपूर्ति करने वाले उपक्रम को होनी चाहिए। निर्दिष्ट शर्त यह है कि उपक्रम द्वारा

खरीदे गए सामान का उपयोग विद्युत ऊर्जा के उत्पादन या वितरण के लिए किया जाना चाहिए। यदि परिस्थितियाँ ऐसी नहीं हैं या शर्तों का पालन नहीं किया जाता है तो माल की बिक्री को कर से छूट नहीं दी जा सकती है। अभिव्यक्ति "ऐसी ऊर्जा का उत्पादन या वितरण" उस स्थिति को निर्दिष्ट करती है जिसके तहत छूट दी गई है। [996 एच, 997 ए-डी]

बिक्री कर आयुक्त, म.प्र. बनाम कपूर डोरी निवार एवं कंपनी, ग्वालियर 22 एसटीसी पी. 152; हिंदुस्तान सेफ्टी ग्लास वर्क्स (पी) लिमिटेड बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य 34 एसटीसी 209, पर चर्चा की गई।

सिविल अपीलिय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 68/1974 और 936/1975।

बिक्री कर संदर्भ संख्या 12 और 11/1969 में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 5-11-1973 से विशेष अनुमति द्वारा अपील।

अपीलकर्ताओं के लिए आर. एस. देसाई, (सीए संख्या 936/75 में), पी.सी. भरतरी, आर. नारायण, के.जे. जॉन, ओसी माथुर।

प्रतिवादी के लिए बी. सेन, (सीए संख्या 68/74 में), और आर.एन.सचथे।

आवेदक/हस्तक्षेपकर्ताओं के लिए पीसी भरतरी (सीए संख्या 68/74 में)।

न्यायालय का निर्णय राय, सीजे द्वारा दिया गया। विशेष अनुमति द्वारा यह अपील इस प्रश्न पर है कि क्या अपीलकर्ता को पंजाब बिक्री कर अधिनियम की धारा 5 (2)(ए)(iv) में निहित प्रावधानों के तहत दिल्ली विद्युत आपूर्ति उपक्रम को पोल और केबल की बिक्री पर अंतर-राज्य कर से छूट प्राप्त है, इसे इसके बाद राज्य अधिनियम के रूप में संदर्भित किया जाएगा।

राज्य अधिनियम की धारा 5(2) (ए)(iv) इस प्रकार है:

"5(2) इस अधिनियम में अभिव्यक्ति "कर योग्य टर्नओवर" का अर्थ किसी भी अवधि के दौरान डीलर के सकल टर्नओवर का वह हिस्सा है जो उसमें से कटौती के बाद बचता है-

(ए) उस अवधि के दौरान उसका कारोबार-

(iv) भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910 के तहत दिए गए लाइसेंस या मंजूरी के तहत जनता को विद्युत ऊर्जा की आपूर्ति करने वाले किसी भी उपक्रम को ऐसी ऊर्जा के उत्पादन या वितरण में उपयोग के लिए वस्तुओं की बिक्री।"

केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम की धारा 8 के तहत, जिसे इसके बाद केंद्रीय अधिनियम के रूप में जाना जाता है, प्रत्येक डीलर, जो अंतर-राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान सरकार को कोई सामान बेचता है; या उप-धारा (3) में निर्दिष्ट विवरण के सरकारी सामान के अलावा किसी पंजीकृत डीलर को बेचता है, तो इस अधिनियम के तहत कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा, जो उसके कारोबार का तीन प्रतिशत होगा।

केंद्रीय अधिनियम की धारा 8(2 ए) में प्रावधान इस प्रकार हैं:-

"धारा 6 की उपधारा (1 ए) या इस धारा की उपधारा (1) या उपधारा (2) में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के तहत एक डीलर द्वारा अपने टर्नओवर पर देय कर, जहां तक टर्नओवर या उसका कोई हिस्सा किसी सामान की बिक्री, बिक्री या, जैसा भी मामला हो, की खरीद से संबंधित है, जो उपयुक्त राज्य के बिक्री कर कानून के तहत, आम तौर पर कर से छूट, या आम तौर पर तीन प्रतिशत से कम दर पर कर के अधीन, (चाहे कर या शुल्क या किसी अन्य नाम से कहा जाए), शून्य होगा या जैसा भी मामला हो, कम दर पर गणना की जाएगी।

स्पष्टीकरण: इस उपधारा के प्रयोजन के लिए किसी भी सामान की बिक्री या खरीद को आम तौर पर उपयुक्त राज्य के बिक्री कर कानून के तहत कर से छूट नहीं माना जाएगा, यदि कानून के तहत ऐसे सामान की बिक्री या खरीद को छूट दी गई है केवल निर्दिष्ट परिस्थितियों में या निर्दिष्ट शर्तों के तहत या ऐसे सामानों की बिक्री या खरीद पर लगाए गए कर से छूट दी जाती है या ऐसे सामानों की बिक्री या खरीद पर निर्दिष्ट चरणों में माल के कारोबार के संदर्भ में या अन्यथा कर लगाया जाता है।"

अपीलकर्ता की ओर से तर्क यह है कि राज्य अधिनियम की धारा 5(2)(ए)(iv) सपठित केंद्रीय अधिनियम की धारा 8(2 ए) के स्पष्टीकरण के कारण अपीलकर्ता को अंतर-राज्य बिक्री कर भुगतान से छूट प्राप्त है। राज्य अधिनियम की धारा 5(2)(ए)(iv) में आने वाले शब्द "ऐसी ऊर्जा के उत्पादन या वितरण में इसके द्वारा उपयोग के लिए सामान" अपीलकर्ता के अधिवक्ता द्वारा सामान का वर्णनात्मक होने के लिए कहा गया है। संक्षेप में, अपीलकर्ता का तर्क यह है कि विद्युत ऊर्जा की आपूर्ति करने वाले उपक्रम द्वारा उपयोग के लिए सामान आम तौर पर कराधान से मुक्त होते हैं, और इसलिए, उन्हें टर्नओवर में शामिल नहीं किया जाना चाहिए।

राज्य की ओर से तर्क यह है कि राज्य अधिनियम की धारा 5(2)(ए)(iv) के तहत दी गई छूट निर्दिष्ट परिस्थितियों और निर्दिष्ट शर्तों के तहत छूट है। निर्दिष्ट परिस्थितियों को भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910 के तहत जनता को विद्युत ऊर्जा की आपूर्ति करने वाले उपक्रम को बिक्री कहा जाता है। निर्दिष्ट शर्तें यह हैं कि सामान्य ऐसी ऊर्जा के उत्पादन या वितरण में उपक्रम द्वारा उपयोग के लिए हैं।

इस अपील में प्रश्न का उत्तर यह है कि क्या राज्य अधिनियम की धारा 5(2)(ए)(iv) में उल्लिखित छूट निर्दिष्ट परिस्थितियों में या निर्दिष्ट शर्तों के तहत है, जैसा भी मामला हो, या यह एक सामान्य छूट है जैसा कि अपीलकर्ता ऐसी ऊर्जा के उत्पादन या वितरण में उपयोग के लिए विद्युत आपूर्ति उपक्रम को माल की बिक्री के मामलों में दावा करता है।

अपीलकर्ता ने राज्य अधिनियम की धारा 6 और विशेष रूप से आइटम 33 और 46 के साथ पठित अनुसूची बी का हवाला दिया ताकि यह स्पष्ट किया जा सके कि निर्दिष्ट परिस्थितियों या निर्दिष्ट शर्तों के तहत क्या छूट होगी। अनुसूची बी में दो कॉलम हैं। पहला कॉलम माल का वर्णन करता है। दूसरा कॉलम उन शर्तों का वर्णन करता है जो वस्तुओं को कर मुक्त बनाती हैं। अनुसूची बी में आइटम 33 में पहले कॉलम में उल्लिखित "एक्सरे फोटोग्राफ सहित फोटोग्राफ" कर मुक्त हैं "जब फोटोग्राफर और उन्हें तैयार करने वाले रेडियोलॉजिस्ट द्वारा बेचे जाते हैं" जैसा कि दूसरे कॉलम

में बताया गया है। आइटम 46 में पहले कॉलम में उल्लिखित "हाथ से काता गया सूत" कर मुक्त हो जाता है "जब इसे ऐसे व्यक्ति द्वारा बेचा जाता है जो विशेष रूप से हाथ से काते गए सूत का व्यापार करता है" जैसा कि दूसरे कॉलम में बताया गया है।

राज्य अधिनियम की धारा 5(2) कर योग्य टर्नओवर से संबंधित है। इसमें कोई विवाद नहीं है कि विद्युत ऊर्जा आपूर्ति करने वाले उपक्रमों को बेचे गए बिजली के खंभे और केबल को राज्य अधिनियम के तहत कर योग्य टर्नओवर में शामिल होने से छूट दी गई है। सवाल यह है कि क्या अंतरराज्यीय व्यापार के दौरान की गई ऐसी बिक्री को भी केंद्रीय बिक्री कर से छूट मिलती है।

अपीलकर्ता का तर्क है कि राज्य अधिनियम में छूट सामान्य है क्योंकि छूट वस्तुओं के संबंध में बिना किसी गणना या वस्तुओं के वर्गीकरण के लागू होती है। इसके अलावा, यह कहा गया है कि छूट सामान्य है क्योंकि बिक्री विद्युत ऊर्जा के उत्पादन और वितरण में उपयोग के लिए है। अपीलकर्ता के अनुसार विद्युत ऊर्जा आपूर्ति करने वाले उपक्रम को सभी वस्तुओं की बिक्री को कर योग्य टर्नओवर में शामिल होने से छूट दी गई है, जब तक कि सामान विवरण का उत्तर नहीं देता है कि वे विद्युत ऊर्जा के उत्पादन या वितरण में उपयोग के लिए हैं।

अपीलकर्ता ने "आम तौर पर कर से छूट" अभिव्यक्ति के अर्थ के समर्थन में बिक्री कर आयुक्त, मध्य प्रदेश बनाम कपूर डोरी निवार एंड कंपनी, ग्वालियर (22 एस.टी.सी.152) में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया। मध्य प्रदेश मामले (सुप्रा) में राज्य सरकार ने वर्ष 1959 में एक अधिसूचना जारी की जिसमें 1958 के प्रासंगिक राज्य अधिनियम के तहत पंजीकृत डीलर द्वारा निवार की बिक्री की एक वर्ष की अवधि के लिए बिक्री कर के भुगतान से छूट दी गई। छूट को बाद में 31 मार्च, 1963 तक बढ़ा दिया गया। निर्धारिती जो एक एक पंजीकृत व्यापारी था, ने निवार की अंतरराज्यीय बिक्री पर छूट का दावा किया। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि छूट की अवधि के दौरान, एक पंजीकृत डीलर द्वारा निवार की बिक्री आम तौर पर केंद्रीय अधिनियम की धारा 8 (2 ए) के अर्थ में कर से मुक्त थी, और इसलिए, निर्धारिती की अंतर-राज्यीय निवार की बिक्री को केंद्रीय अधिनियम के तहत कर से छूट दी गई थी। केंद्रीय अधिनियम की धारा 8(2 ए) के स्पष्टीकरण में होने वाली अभिव्यक्ति "केवल निर्दिष्ट परिस्थितियों में या निर्दिष्ट शर्तों के तहत छूट" का अर्थ ऐसी परिस्थितियों या शर्तों से है, जिनका अस्तित्व या गैर-अस्तित्व छूट देने से रोकता है। दूसरे शब्दों में, यदि वे परिस्थितियाँ मौजूद नहीं हैं या उन शर्तों का पालन नहीं किया जाता है, तो माल की बिक्री को कर से छूट नहीं दी जा सकती है, भले ही वे डीलरों के एक वर्ग द्वारा की

गई हों, जिन्हें छूट दी गई है और उस अवधि के दौरान जिसके लिए छूट दी गई है।

मध्य प्रदेश मामले (सुप्रा) में इस विषय पर कोई विवाद नहीं था कि निर्धारिती द्वारा की गई बिक्री केंद्रीय अधिनियम की धारा 8(1) के अंतर्गत आती है। राज्य अधिनियम ने एक पंजीकृत डीलर द्वारा की गई निवार की बिक्री पर बिक्री कर से छूट दी। अधिसूचना के तहत एक पंजीकृत डीलर द्वारा बिक्री पर दी गई छूट बिना किसी प्रतिबंध या सीमा के थी, जहां तक एक पंजीकृत डीलर द्वारा बिक्री का संबंध था। यद्यपि छूट की अवधि निश्चित थी, परंतु इसे छूट के संबंध में लगाई गई शर्त नहीं माना गया। वहां यह भी तर्क दिया गया कि क्योंकि छूट पंजीकृत डीलरों को दी गई थी, छूट डीलरों के एक वर्ग को दी गई थी, और इसलिए, इसे निर्दिष्ट परिस्थितियों में या निर्दिष्ट शर्तों के तहत छूट माना जाना चाहिए। न्यायालय ने यह कहते हुए विवाद को खारिज कर दिया कि छूट सभी पंजीकृत डीलरों को बिना किसी प्रतिबंध या शर्त के थी।

दूसरा निर्णय जिस पर अपीलकर्ता ने भरोसा किया वह हिंदुस्तान सेफ्टी ग्लास वर्क्स (प्रा.) लिमिटेड बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य (34 एस.टी.सी. 209) मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय का है। सेफ्टी ग्लास वर्क्स मामले में (सुप्रा) कंपनी द्वारा इसके कारखानों में शीशे और दर्पण का निर्माण किया जाता था। राज्य अधिनियम के तहत राज्य सरकार द्वारा

जारी एक अधिसूचना के तहत दर्पण और ना टूटने वाले काँच की बिक्री या तो ऐसे सामान के आयातक द्वारा बिक्री के बिंदु पर या उसके निर्माता द्वारा बिक्री के बिंदु पर बिक्री कर के लिए उत्तरदायी थी। इसके बाद, राज्य सरकार द्वारा एक अधिसूचना जारी की गई जिसमें कंपनी द्वारा इलाहाबाद में निर्मित टफन्ड ग्लास और दर्पणों को तीन साल की अवधि के लिए बिक्री कर के भुगतान से छूट दी गई। कंपनी ने दावा किया कि उसके द्वारा निर्मित टफन्ड ग्लास और दर्पणों की बिक्री का टर्नओवर, आम तौर पर राज्य अधिनियम के तहत कर से मुक्त होने के कारण, केंद्रीय अधिनियम की धारा 8 (2 ए) में निहित प्रावधानों के कारण केंद्रीय बिक्री कर के लिए भी उत्तरदायी नहीं है। यह माना गया कि केंद्रीय अधिनियम की धारा 8 (2 ए) के प्रयोजनों के लिए, कंपनी द्वारा निर्मित दर्पणों और टफन्ड ग्लासों की बिक्री किसी भी स्थिति में और किसी भी परिस्थिति में कंपनी के हाथों कर के अधीन नहीं थी। दिए गए कारण यह थे कि आम तौर पर यह माना जाएगा कि कंपनी द्वारा दर्पण और टफन्ड ग्लास की बिक्री को आम तौर पर छूट दी गई थी जब तक कि यह नहीं दिखाया जा सके कि ऐसा सामान केंद्रीय अधिनियम की धारा 8 (2 ए) के स्पष्टीकरण में निर्दिष्ट वर्ग से संबंधित था। चूंकि कंपनी द्वारा निर्मित टफन्ड ग्लास और दर्पण ऐसी श्रेणी में नहीं आते थे, इसलिए कंपनी के प्राधिकार में उन वस्तुओं की बिक्री का कारोबार केंद्रीय अधिनियम के तहत कर के लिए उत्तरदायी नहीं था।

सेफ्टी ग्लास वर्क्स मामले (सुप्रा) में अधिसूचना में यह शर्त है कि ऐसी बिक्री का कारोबार तीन साल की अवधि के लिए बिक्री कर के भुगतान से मुक्त होगा जिसका अर्थ ये नहीं है कि निर्दिष्ट परिस्थितियों या निर्दिष्ट शर्तों के तहत ऐसे माल के कारोबार को कर से छूट दी जाएगी।

राज्य अधिनियम की धारा 6 छूट की बात नहीं करती है, बल्कि कर मुक्त वस्तुओं से संबंधित है। दूसरे शब्दों में, धारा 6 उन निर्दिष्ट वस्तुओं से संबंधित है जिन पर कोई कर देय नहीं है। राज्य अधिनियम की धारा 5 इस बात से संबंधित है कि डीलर के कर योग्य टर्नओवर में किसे शामिल नहीं किया जाना चाहिए।

दोनों धाराएँ उन वस्तुओं से संबंधित हैं जिन पर बिक्री कर नहीं लगता है। केंद्रीय अधिनियम की धारा 8(2 ए) वस्तुओं को अंतरराज्यीय बिक्री कर से छूट देती है, जहां राज्य के कर कानून ने उन्हें बिक्री कर से छूट दी है। केंद्रीय अधिनियम की धारा 8(2 ए) का स्पष्टीकरण उस छूट को हटा देता है जहां यह सामान्य नहीं है और निर्दिष्ट परिस्थितियों में या निर्दिष्ट शर्तों के तहत दी गई है। राज्य अधिनियम की धारा 5 (2) (ए) (iv) में निहित प्रावधान उन बिक्री को बाहर करते हैं जो निर्दिष्ट परिस्थितियों या निर्दिष्ट शर्तों के तहत की जाती हैं। निर्दिष्ट परिस्थितियाँ यह हैं कि बिक्री भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910 के तहत दिए गए लाइसेंस या मंजूरी के तहत जनता को विद्युत ऊर्जा की आपूर्ति करने वाले

उपक्रम को की जानी चाहिए। निर्दिष्ट शर्त यह है कि उपक्रम द्वारा खरीदे गए सामान का उपयोग विद्युत ऊर्जा का उत्पादन या वितरण में किया जाना चाहिए। यदि ऐसी परिस्थितियाँ मौजूद नहीं हैं या शर्तों का पालन नहीं किया जाता है तो माल की बिक्री को कर से छूट नहीं दी जा सकती है। सामान्य छूट का मतलब है कि केंद्रीय बिक्री कर लगाने से समान छूट उपलब्ध होने से पहले माल को कर से पूरी तरह मुक्त किया जाना चाहिए। जहां कराधान से छूट शर्तों द्वारा या कुछ परिस्थितियों में प्रदान की जाती है, वहां आम तौर पर कर से कोई छूट नहीं होती है।

अपीलकर्ता का यह तर्क कि राज्य अधिनियम की धारा 5(2)(ए)(iv) में "ऐसी ऊर्जा के उत्पादन या वितरण में" शब्द वस्तुओं का वर्णनात्मक हैं, अस्वीकार्य है। अभिव्यक्ति "ऐसी ऊर्जा का उत्पादन या वितरण" उस स्थिति को निर्दिष्ट करती है जिसके तहत छूट दी गई है।

इन कारणों से हमारी राय है कि उच्च न्यायालय यह मानने में सही था कि विद्युत ऊर्जा की आपूर्ति करने वाले उपक्रमों की बिक्री आम तौर पर राज्य अधिनियम की धारा 5(2) (ए)(iv) सपठित केंद्रीय अधिनियम की धारा 8(2 ए) के अर्थ में कर से मुक्त नहीं थी। अपील खारिज की जाती है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि उच्च न्यायालय ने पक्षकारों को अपनी लागत वहन करने और भुगतान करने का निर्देश दिया था, इसी तरह का आदेश यहां भी दिया जाता है। अपील खारिज।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' के जरिए अनुवादक खुशबू सोनी द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय वादी के प्रतिबंधित उपयोग के लिए उसकी भाषा में समझाने के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।